



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1939 (श10)

(सं0 पटना 612) पटना, शुक्रवार, 14 जुलाई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

1 जून 2017

सं० 22/नि0सि0(मुज0)-06-06/2016-823—श्री ओम प्रकाश अम्बरकर (आई0डी0 सं०-3467) तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त सह अध्यक्ष, गंडक कांडा, मुजफ्फरपुर के उनके उक्त पद पर पदस्थापन अवधि के दौरान श्री राजेश्वर नाथ वर्मा, आशुटंकक (सेवानिवृत्त) गंडक कांडा, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में नियम विरुद्ध ढग से कार्यवाई कर श्री वर्मा को संरक्षण देने तथा मामले में अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में अभिरुची नहीं लेने जाने के आरोपों से संबंधित आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त पत्र की सम्यक विभागीय समीक्षोपरांत प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1248, दिनांक 01.07.2016 द्वारा श्री अम्बरकर से स्पष्टीकरण पूछा गया।

उक्त के आलोक में श्री अम्बरकर, तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त सह अध्यक्ष गंडक, कांडा मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक-576/5488/16 दिनांक 08.08.16 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कही गयी हैं :-

(1) श्री राजेश्वर नाथ वर्मा, आशुटंकक, गंडक कांडा, मुजफ्फरपुर मेरे पदस्थापन के पूर्व से ही आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के आवासीय कार्यालय पर निजी सहायक के रूप में कार्यरत थे उनके कार्यरत अवधि में बिल सरकारी आदेश के अनाधिकृत रूप से पेड़ के की गयी कटाई के मामले में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध काजी मुहम्मदपुर थाना मुजफ्फरपुर में प्राथमिकी (थाना कांड सं०-477/14) दर्ज कराने के पश्चात आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-570, दिनांक 31.01.2015 द्वारा श्री वर्मा की सेवा वापस करते हुए परामर्श दिया गया कि आयुक्त के सरकारी आवास परिसर से अनधिकृत रूप से पेड़ों की कटाई में श्री वर्मा की संलिप्तता होने पर श्री वर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई जाय।

(2) आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त पत्र के आलोक में श्री वर्मा के विरुद्ध प्रपत्र "क" गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी, जिसमें श्री मुन्नीलाल रजक, अधीक्षण अभियंता-1, गंडक कांडा, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री वर्मा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन अपने पत्रांक-903, दिनांक 29.07.2015 द्वारा समर्पित किया गया।

(3) संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में नियमानुसार उचित निर्णय लेने हेतु कांडा के अधिवक्ता श्री सतीश चन्द्र झा-3, माननीय उच्च न्यायालय, पटना से विधिक परामर्श प्राप्त किया गया। प्राप्त विधिक

परामर्श के आलोक में मेरे कार्यालय आदेश सं०-1049, दिनांक 10.09.2015 द्वारा लिये गये निर्णय का संसूचन आयुक्त के सचिव को की गयी।

(4) आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-6828, दिनांक 26.09.2015 द्वारा कारण पृच्छा करते हुए निदेशित किया गया कि विभागीय कार्यवाही एवं अपराधिक मुकदमा दोनों अलग-अलग है। ऐसी स्थिति में विभागीय कार्यवाही को अपराधिक मुकदमा के कारण रोकने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें अविलंब सुधारात्मक कार्रवाई अपेक्षित है। विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र विधिवत रूप से गठित होना चाहिए। उसमें मात्र FIR को ही **Verbaton** उतारने या मात्र उसी के आधार पर प्रपत्र 'क' गठित करना सुमूल है। उक्त पत्र के आलोक में मेरे द्वारा सभी वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए संसूचित किया गया कि मेरे द्वारा श्री वर्मा के विरुद्ध सभी आवश्यक कार्रवाई नियम संगत की गयी है। फिर भी इसमें मेरी क्या संलिप्तता है। कृपया स्पष्ट किया जाय। किन्तु आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा बिना स्थिति स्पष्ट करते हुए विमर्श करने हेतु तिथि निर्धारित की गयी। मेरे द्वारा निर्धारित तिथि को आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर विमर्श भी किया गया। लेकिन उनके द्वारा इस मामले पर विमर्श के पश्चात किसी प्रकार के अपने परामर्श/निदेश से अवगत नहीं कराया गया। इसी कारण मेरे द्वारा कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं की गयी। जहाँ तक श्री वर्मा को सेवांत लाभ देने का प्रश्न है मेरे द्वारा श्री वर्मा को कोई सेवांत लाभ का भुगतान नहीं किया गया है।

श्री अम्बरकर, तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष गंडक कांडा, मुजफ्फरपुर से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2204, दिनांक 04.10.2016 द्वारा आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से मंतव्य की मांग की गयी। जिसके आलोक में आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में अपने पत्रांक-5482, दिनांक 06.12.2016 द्वारा अपना मंतव्य विभाग में समर्पित किया गया। जिसमें निम्न बातें कही गयी हैं :-

श्री ओम प्रकाश अम्बरकर, तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष गंडक कांडा, मुजफ्फरपुर के स्पष्टीकरण तथा पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 1992, दिनांक 06.05.2016 द्वारा सूचित की गयी स्थितियों की समीक्षा के आलोक में कहना है कि प्रस्तुत मामले में श्री अम्बरकर द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मूल रूप से अपनी कार्यवाही को विधि परामर्श के आधार पर किये जाने के कारणों से उचित बताया गया है। परंतु प्रस्तुत मामले में विधि परामर्श यह था कि जब आपराधिक मुकदमा/विभागीय कार्यवाही की जा रही है तो विभागीय कार्यवाही नहीं चलायी जा सकती है एवं यह विधि परामर्श स्पष्ट रूप से स्थापित वैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल था। फिर भी श्री अम्बरकर द्वारा इस विधि परामर्श पर अपना विवेकपूर्ण निर्णय न लेकर आँख मूंदकर उस परामर्श को मान लिया गया जो न सिर्फ उनके **Non-application of mind** का द्योतक है बल्कि इससे यह प्रतीत होता है यह विधि परामर्श **procured** था तथा इस मामले में भी श्री अम्बरकर की भी संलिप्तता थी।

श्री अम्बरकर, तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त सह अध्यक्ष गंडक कांडा, मुजफ्फरपुर से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये हैं :-

श्री अम्बरकर के स्पष्टीकरण के साथ संलग्न कागजात के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्री राजेश्वर नाथ वर्मा, आशुटंकक के विरुद्ध आयुक्त के आवासीय परिसर से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के मामले में प्रपत्र- 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस मामले में संचालन पदाधिकारी सह-अधीक्षण अभियंता-1, गंडक कांडा, मुजफ्फरपुर द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें आरोप के संदर्भ में किसी प्रकार के मंतव्य का गठन नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी ने कहा है कि आयुक्त के आवासीय कार्यालय परिसर से पेड़ों की कटाई के आरोप में श्री वर्मा के विरुद्ध मुहम्मदपुर थाना कांड सं०-477/2014 पंजीकृत कराया गया है। इस बाढ़ में श्री वर्मा माननीय उच्च न्यायालय, पटना से अग्रिम जमानत प्राप्त करने के पश्चात व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर से स्थायी जमानत प्राप्त कर चुके हैं। यह मामला माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के निर्णय पर अग्रेतर कार्रवाई करना उचित होगा। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री वर्मा के सभी सेवांत लाभों का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री राजेश्वर नाथ वर्मा, आशुटंकक की प्रतिनियुक्ति आयुक्त आवासीय कार्यालय में की गयी थी। आयुक्त के आवासीय परिसर से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की गयी। जिसमें जाँचोपरांत श्री वर्मा के संलिप्तता होने का मामला प्रकाश में आया। फलस्वरूप श्री वर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी एवं आयुक्त के द्वारा श्री वर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु क्षेत्रीय विकास आयुक्त सह अध्यक्ष गंडक कांडा को निदेशित किया गया। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर श्री वर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। किंतु इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी में यह कहते हुए किसी प्रकार का मंतव्य गठित नहीं किया गया कि यह मामला माननीय न्यायालय के यहाँ विचाराधीन है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प ज्ञापांक-3/M0162/05 का0-2324 दिनांक 10.07.2007 में निदेशित किया गया है कि आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवक के मामले में आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ किया जाय। सम्पूर्ण मामले में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा दिये गये निदेश की अनदेखी की गयी है। यदि संचालन पदाधिकारी द्वारा अभिमत गठित किये बगैर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया था तो श्री अम्बरकर तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त सह अध्यक्ष गंडक कांडा को चाहिए था कि वे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के इस संकल्प की ओर संचालन पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट

करते हुए जाँच प्रतिवेदन वापस कर देते, किन्तु श्री अम्बरकर द्वारा ऐसा नहीं किया गया। नतीजतन आरोपी श्री वर्मा के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी और वे सभी सेवांत लाभों को प्राप्त करने में भी सफल रहे। इस पूरे प्रकरण में श्री अम्बरकर की भूमिका आरोपित पदाधिकारी श्री वर्मा को बचाने की है। जिसके लिए श्री अम्बरकर दोषी हैं।

अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री ओम प्रकाश अम्बरकर, तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष गंडक कांडा, मुजफ्फरपुर को निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

"तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"

उक्त निर्णय के आलोक में श्री ओम प्रकाश अम्बरकर, तत्कालीन क्षेत्रीय विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष गंडक कांडा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

"तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 612-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>